

अनुलग्नकों की सूची

- अनु. क्र. 1.1 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना
- अनु. क्र. 1.2 सचिव, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति आदेश
- अनु. क्र. 1.3 राज्य वित्त आयोग हेतु संदर्भ शर्तें
- अनु. क्र. 1.4 आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की प्रथम अधिसूचना
- अनु. क्र. 1.5 आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की द्वितीय अधिसूचना
- अनु. क्र. 1.6 आयोग के संभागस्तरीय / जिला स्तरीय बैठकों की जानकारी
- अनु. क्र. 1.7 राज्य शासन के पदाधिकारी जिनसे आयोग द्वारा चर्चा की गयी
- अनु. क्र. 1.8 राज्य वित्त आयोग द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं / सेमीनारों में भागीदारी
- अनु. क्र. 3.1 छत्तीसगढ़ राज्य बजट के अनुसार कर वसूली व्यय की गणना
- अनु. क्र. 3.2 समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में राज्य की स्वयं की आय में से सीधे स्थानीय निकायों को वास्तविक अंतरित राशि का विवरण
- अनु. क्र. 3.3 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि का आंकलन
- अनु. क्र. 3.4 तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की कृत कार्यवाही प्रतिवेदन
- अनु. क्र. 6.1 प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या
- अनु. क्र. 6.2 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जिला पंचायतों की औसत जनसंख्या
- अनु. क्र. 6.3 छत्तीसगढ़ राज्य में पेसा ग्राम पंचायतों की सूची
- अनु. क्र. 6.4 जिला स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या
- अनु. क्र. 6.5 जनगणना 2011 के अनुसार नगर निगम की जनसंख्या
- अनु. क्र. 6.6 जनगणना 2011 के अनुसार नगर पालिका परिषद की जनसंख्या
- अनु. क्र. 6.7 जनगणना 2011 के अनुसार नगर पंचायत की जनसंख्या
- अनु. क्र. 7.1 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार
- अनु. क्र. 7.2 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता
- अनु. क्र. 7.3 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति
- अनु. क्र. 7.4 जल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मापदंड
- अनु. क्र. 7.5 जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति

- अनु. क्र. 7.6 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट निराकरण
- अनु. क्र. 7.7 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट योजना की स्थिति
- अनु. क्र. 7.8 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी तथा मितानिन
- अनु. क्र. 7.9 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धता
- अनु. क्र. 8.1 आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क अधिरोपण की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010
- अनु. क्र. 11.1 उड़ीसा शासन के स्थानीय निकायों को उड़ीसा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राशि हस्तांतरण संबंधी आदेश
- अनु. क्र. 12.1 स्तरांक की गणना हेतु आवश्यक आंकड़े एवं स्तरांक के गणना की जानकारी
- अनु. क्र. 12.2 छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या
- अनु. क्र. 12.3 ग्राम पंचायतों के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय की गणना
- अनु. क्र. 12.4 नगरीय निकायों के बकाया कच्ची सड़कों को पक्का करने की लागत
- अनु. क्र. 12.5 नगरीय निकायों में बकाया नाली रहित सड़कों पर नाली बनाने की लागत
- अनु. क्र. 12.6 बकाया प्रकाश रहित सड़कों पर स्ट्रीट लाईट लगाने की लागत
- अनु. क्र. 12.7 नगरीय निकायों की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय
- अनु. क्र. 12.8 पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियाँ
- अनु. क्र. 12.9 पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ (वर्ष 2017-18 से 2021-22)
- अनु. क्र. 12.10 पंचायती राज संस्थाओं की 2025-26 से 2029-30 तक विभिन्न मदों से प्रक्षेपित प्राप्तियाँ
- अनु. क्र. 12.11 नगरीय निकायों की स्वयं की स्रोत से कुल आय
- अनु. क्र. 12.12 नगरीय निकायों की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ (वर्ष 2017-18 से 2021-22)
- अनु. क्र. 12.13 नगरीय निकायों की 2025-26 से 2029-30 तक विभिन्न मदों से संभावित (प्रक्षेपित) प्राप्तियाँ
- अनु. क्र. 12.14 100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण करने पर प्रक्षेपित प्राप्तियाँ
- अनु. क्र. 12.15 स्थानीय निकायों को समनुदेशिक प्राप्तियों के रूप में देय/कर/उपकर अधिभार राशि

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

रायपुर, बुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021 — श्रावण 8, शक 1943

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री सरजियस मिज, अध्यक्ष होंगे।

- आयोग के अध्यक्ष, ऐसी तारीख, जिस पर वे पदभार ग्रहण करते हैं, से 31 जुलाई, 2023 तक पद धारण करेंगे।
- आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।
- आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद मिश्रा, उप-सचिव,

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 37, दिनांक 29 जुलाई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद मिश्रा, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

39

अटल नगर, दिनांक 2 / 02 / 2022

क्रमांक 87 / 1037 / 2021 / स्था. / चार :: राज्य शासन, एतद्वारा श्री सतीश पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर सचिव, (छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी) वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में प्राक्धान अनुसार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर के पद पर एक वर्ष के लिए सविदा नियुक्ति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


22/2/2022

(प्रेमा गुलाब एक्का)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

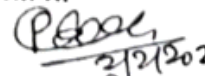
अटल नगर, दिनांक 2 / 02 / 2022

पृ. क्र. 88 / 1037 / 2021 / स्था. / चार,

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
05. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
06. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
07. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
08. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
10. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (वित्त आयोग प्रकोष्ठ), मंत्रालय, अटल नगर
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, नवा रायपुर/रायपुर
12. संबंधित अधिकारी -----
13. आदेश फोल्डर

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


22/2/2022

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:मंत्रालय:—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—00—

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 मार्च, 2022

क्रमांक 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 — यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुए, अधिसूचना क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ एवं 243 में द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा—

1. (क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में—

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किए जायें को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो), के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्याप्यों और अनुशंसाएं करने सहित निम्नलिखित के संबंध में—

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को

चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहीत करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

- (दो) स्थानीय शासन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;
 - (तीन) स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;
 - (चार) स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;
 - (पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने; और
 - (छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने।
- (ग) स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने की आवश्यकता;
- (घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाएं।
2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:-
- (एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;
 - (दो) स्थानीय निकायों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और
 - (तीन) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी जा रही निधियां।
3. आयोग यह बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।
4. आयोग उपरोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2023 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पूजा शुक्ला)

उपसचिव
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—00—

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई, 2023

क्र. 39/आर-14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243अ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 एवं अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, —

सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक "31 जुलाई, 2023" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "31 अक्टूबर, 2023" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(पूजा शुक्ला)
उप सचिव
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—00—

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी, 2024

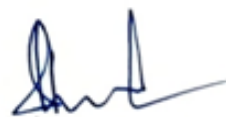
क्र. 02/आर-14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021, अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 तथा अधिसूचना क्र. 39/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 28 जुलाई 2023 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, –

सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक “31 अक्टूबर, 2023” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “31 जनवरी, 2024” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(पूजा शुक्ला)

उप सचिव
वित्त विभाग

स्थानीय निकायों के साथ आयोजित बैठकों का विवरण		
क्र.	स्थान	दिनांक
01	बस्तर संभाग	12-13 अप्रैल, 2022
02	बिलासपुर संभाग	28-29 अप्रैल, 2022
03	सरगुजा संभाग	19-20 मई, 2022
04	दुर्ग संभाग	16-17 जून, 2022
05	रायपुर संभाग	07-08 जुलाई, 2022
06	राजनांदगांव	14 अक्टूबर, 2022
07	जशपुर	31 अक्टूबर, 2022
08	सारंगढ़-रायगढ़	19-20 जनवरी 2023
09	नारायणपुर	09 फरवरी, 2023
10	कांकेर	10 फरवरी, 2023
11	जनपद पंचायत दुलदुला, कुनकुरी	15 मई, 2023
12	बचेली, दंतेवाड़ा	22-23 अगस्त 2023

अनुलग्नक - 1.7

राज्य शासन के पदाधिकारी जिनसे आयोग द्वारा चर्चा की गई

- 1 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग –
 - अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 - संचालक, संचालनालय पंचायत
 - निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, छत्तीसगढ़
 - उप संचालक, पंचायत संचालनालय
2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग –
 - प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 - संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
3. वित्त विभाग –
 - सचिव, वित्त विभाग
 - आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा
4. स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग
 - अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
 - उप संचालक, महिला एवं बाल विकास
5. लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग
 - मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. आबकारी विभाग
 - संचालक, आबकारी विभाग
7. मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग
 - महानिदेशक, मुद्रांक
 - संयुक्त संचालक वित्त, मुद्रांक एवं पंजीयन

राज्य वित्त आयोग द्वारा विभिन्न सेमिनार में भागीदारी

1. Indian Institute of Public Finance & Policy (NIPFP) New Delhi o UNICEF के तत्वाधान में Need and Significance of Including Child indicators in the Devolution formulae by the State Finance Commissions विषय पर आयोजित कन्सल्टेशन वर्कशॉप, दिनांक 22 अप्रैल 2022 में भाग लिया गया।
2. National Institute of Rural Development & Panchayati Raj हैदराबाद के तत्वाधान में National Conclave on State Finance Commissions विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार, दिनांक 29-30 नवंबर 2022 में भाग लिया गया।
3. Indian Institute of Public Finance & Policy (NIPFP) o UNICEF के तत्वाधान में "Mainstreaming Children Priorities in Planning - Integrating Child Related Indicators into State Finance Commissions' Recommendations" विषय पर दिनांक 08.08.2023 को एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया गया।
4. सेंटर फॉर अर्बन स्टडीस, Indian Institute of Public Administration (IIPA) दिल्ली के साथ दिनांक 25. 09.2023 को चर्चा में भाग लिया गया।

राज्य के कर वसूली व्यय की गणना

(राशि हजार रू. में)

क्र.	वर्ष	राजस्व विभाग 0029 भू-राजस्व		परिवहन 0041 वाहनो पर कर		ऊर्जा 0043 बिजली पर कर एवं शुल्क	वाणिज्यिक कर 0006 राज्य 0023 होटल प्राप्ति 0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर 0030 स्टाम्प एवं पंजीयन 0039 राज्य उत्पाद शुल्क 0040 विक्री व्यापार आदि पर कर 0042 माल एवं यात्रियों पर कर 0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क		योग		कुल प्राप्ति में संग्रहण लागत का प्रतिशत
		कर प्राप्ति	संग्रहण लागत	कर प्राप्ति	संग्रहण लागत		कर प्राप्ति	संग्रहण लागत	कुल कर प्राप्ति	कुल संग्रहण लागत	
1	2017-18	4464118	2434730	11800136	148316	16889545	165793019	1818351	198946818	4480940	2.25
2	2018-19	4875714	2639385	12048504	184553	17902737	179445584	1623344	214272539	4534241	2.12
3	2019-20	5515021	3016892	12748516	201559	18370037	184544901	1750690	221178475	5059434	2.29
4	2020-21	9377141	2968425	11480655	173456	2341411	184620060	1618707	228891967	4845675	2.12
5	2021-22	9000000	3946940	16000000	374802	27000000	223000000	2370963	275000000	6807580	2.48
औसत											2.25

स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न वर्षों के बजट

समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में राज्य की स्वयं की आय में से सीधे स्थानीय निकायों को वास्तविक अंतरित राशि का विवरण

(राशि हजार ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	ग्रामीण स्थानीय निकाय	नगरीय स्थानीय निकाय			योग	कुल योग
		स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अंतरण	शुल्क, अंतरण एवं अन्य प्राप्तियाँ	प्रवेश कर से अनुदान	एफ.एल. लाईसेंस फीस से अनुदान		
1	2017-18	0	690000	12042000	355000	13087000	13087000
2	2018-19	247209	490151	7915240	127557	8532948	8780157
3	2019-20	554430	713450	10000000	171000	10884450	11438880
4	2020-21	605658	763391	10000000	171000	10934391	11540049
5	2021-22	700000	1024537	9680000	188100	10892637	11592637
	योग	2107297	3681529	49637240	1012657	54331426	56438723

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि का आंकलन

(राशि हजार ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	राज्य की स्वयं के करों से आय	संग्रहण लागत	स्वयं की कर आय से समनुदेशिक प्राप्तियों के रूप में स्थानीय निकायों को सीधे हस्तांतरण	राज्य की स्वयं की करों से प्राप्त शुद्ध आय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अंतरण हेतु पात्र राशि	प्रतिशत	वास्तविक
1	2017-18	198946818	4480940.00	13087000	181378878.00	14510310.24	8	1387.27
2	2018-19	214272539	4534241.00	8780157	200958141.00	16076651.28	8	1138.83
3	2019-20	221178475	5059434.00	11438880	204680161.00	16374412.88	8	1069.20
4	2020-21	228891967	4845675.00	11540049	212506243.00	19125561.87	9	1059.54
5	2021-22	270837300	6807580.00	11592637	252437083.00	22719337.00	9	1331.71
	योग	1134127099	25727870.00	56438723.00	1051960506.00	88806273.27		5986.55

*2017-2018 से 2019-2020 तक द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 8% की दर से

*2020-2021 से 2021-2022 तक तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 9% की दर से

स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न वर्षों के बजट पत्र

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की कृत कार्यावाही प्रतिवेदन(ATR)

1.	4.35	आयोग की अनुशंसा है कि पेसा क्षेत्र में स्थापित समितियों के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के मध्य प्रभावी समन्वय के लिये राज्य शासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश/आदेश जारी किये जाने चाहिये।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की कृत कार्यावाही प्रतिवेदन (ATR) पेसा अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन हेतु बनाये जा रहे छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021 में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 46 के अंतर्गत गठित स्थायी समितियों को ग्राम सभा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर किसी अन्य समितियों के गठन नहीं कर सकने का प्रावधान रखा गया है।
2.	4.40	छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को रखी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पंचायतों को दिये जाने वाले अनुसूचित 29 विषयों को अधिकांश शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। कुछ विभागों द्वारा पहल की गई है, परन्तु उनके द्वारा कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है। अतः आयोग का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित कार्यकलाप चित्रण का पूरी शिद्दत के साथ पालन किया जाय। आयोग की अनुशंसा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाय, जो पंचायती राज संस्थाओं को निधियों कार्यों एवं कमियों के प्रत्यायोजन/अंतरण की पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखे कि जिससे स्थानीय शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिये उपचारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दे सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अनुलग्नक - 3.4 अधिकारों का विकेन्द्रीकरण के संबंध में 29 विभागों को पत्र का लेख किया गया है। वर्तमान समय में विभागों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के लिये 29 विषयों को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है।

3.	4.41	आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ शासन कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया को समयबद्ध रीति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के 29 विषयों से संबंधित प्राथमिकता के गतिविधियों का चयन कर लक्ष्य पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है।
4.	5.16	आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों के पद रिक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है। आयोग की अनुशंसा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की जाय एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध कराई जाय।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	वर्तमान में आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी के 1667 स्वीकृत पद के विरुद्ध 830 पद ही भरे हुए हैं। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से पृथक होकर पंचायत संचालनालय के गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ पंचायत तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम नहीं बन पाने के कारण उक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। भर्ती नियम के प्रस्ताव वर्ष 2020 से सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग में लंबित है।
5.	5.27	आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त कर्म की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिसे लेखों एवं कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान हो।	वित्तीय भार के दृष्टिगत चरणबद्ध प्रक्रिया में पंचायतों के राजस्व अर्जन के आधार पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पूर्व में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत प्रदेश के 7043 ग्राम पंचायतों में 5000/- रुपये प्रतिमाह के मानदेय में पंचायत सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती की गई थी। उक्त योजना समाप्त होने के पश्चात् बजट के अभाव में उक्त पदों को निरंतर नहीं किया जा सका। वर्तमान में आरजीएसए योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने हेतु प्रतिमाह 50,000/- रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
6.	5.28	आयोग की अनुशंसा है कि कुछ पंचायतों में पायलेट परियोजना के रूप में ग्राम सभा की कार्यवाही की "वायस रिकार्डिंग" की जा सकती है। इससे ग्राम सभा के क्रियाकलापों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	ग्राम सभा आयोजन हेतु राज्य/जिला स्तर से जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत ग्राम सभा की कार्यवाही का वायस रिकार्डिंग हेतु निर्देश जारी किया जा सकता है।

7.	5.33	आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कोषों का आबंटन पारदर्शी तथा मानक आधार पर किया जाना चाहिए।	निर्धारित कोषों का पारदर्शी तथा मानक आधार पर आबंटन हेतु सहमति दी गई है।	- वित्त विभाग - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 में पंचायती राज संस्थाओं लिए 6.91 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किये जाने का अनुशंसा है जो वर्तमान में अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पारदर्शिता हेतु केन्द्र शासन के योजनाओं के भाति राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि को पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
8.	6.9	तृतीय राज्य वित्त आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा नल-जल योजना हेतु दिये जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाय एवं वर्ष में दो बार अनुदान उपलब्ध कराया जाय। राज्य शासन अनुशंसा के अनुपालन को भी सुनिश्चित करायें।	वर्ष में दो बार अनुदान देने का पालन किया जा रहा है। दो-दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षण की अनुशंसा को मान्य किया गया है।	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	
9.	6.30	आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अधिनिर्णय अवधि में रुपये 20.00 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाय। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिये एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अनाबद्ध रखा जाय। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिये उचित दिशा-निर्देश जारी करें।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	- वित्त विभाग - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	आयोग की अनुशंसा के आधार पर जनपद पंचायत विकास निधि योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गई, जिसमें प्रति जनपद पंचायत 50.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रति जनपद पंचायत 20.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 से इस योजना के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए जनपद अध्यक्ष के लिए 5.00 लाख, उपाध्यक्ष के लिए 3.00 लाख जनपद सदस्य के लिए 2.00 लाख रुपये निधि का प्रावधान रखते हुए उक्त मद में 65.42 करोड़ का बजट आबंटन दिया गया है।

10.	7.4	आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक तालाब निस्तारी प्रयोजन के लिये आरक्षित रखा जाना चाहिए और मत्स्य पालन के उद्देश्य के लिये पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	वर्तमान में प्रत्येक गाँव में एक तालाब निस्तारी के प्रयोजन के लिए आरक्षित रखने के पश्चात् ही शेष तालाब को लीज अथवा पट्टे पर दिया जाता है।
11.	7.18	आयोग की अनुशंसा है कि कर वसूली की वर्तमान प्रक्रिया में स्व-सहायता समूह एवं अन्य समूह को जोड़े जाने की परम्परा को और विकसित किया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-77 के अनुसार ग्राम पंचायतों में अनिवार्य, वैकल्पिक एवं अन्य फीस आरोपित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त करों की वसूली ग्राम – पंचायतों के माध्यम से की जा रही है। उक्त करों की वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्व-सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है।
12.	7.28	आयोग अनुशंसा करता है कि शासन योजनाओं की संख्या न्यूनतम करे जिससे कोषों का अपव्यय नियंत्रित किया जा सके और लक्ष्य एवं संभावित परिणामों में स्पष्टता आ सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	- वित्त विभाग - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - नगरीय प्रशासन विभाग	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, पंचायत पुरस्कार योजनाओं को बंद करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को पुरस्कार एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में 25 राज्य प्रवर्तित योजना से संचालित की जा रही है। समीक्षा उपरांत उद्देश्य पूर्ण होने पर इन योजनाओं को समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

13.	10.17	आयोग की अनुशंसा है कि राज्य को पंचायतों के लिये ई-गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करनी चाहिए एवं ई-लोकल गवर्नेंस प्रणाली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये एक समग्र योजना बनानी चाहिए।	समग्र योजना बनाने की अनुशंसा को मान्य किया गया है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी करने हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों की मूलभूत जानकारी, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, ऑडिट आदि समस्त कार्य किये जा रहे हैं।
14.	11.8	आयोग की यह अनुशंसा है कि नगर पंचायतों का गठन 10,001 से 30,000 तक जनसंख्या वाले नगरों, नगर पालिक परिषद का गठन 30,001 से 2,00,000 जनसंख्या तक एवं नगर पालिक निगम का गठन 2,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाये।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/02/2003 के अनुरूप नगरीय निकायों का गठन 2001 की जनसंख्या पर आधारित था। वर्तमान में जनगणना वर्ष 2021 के आकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा, उच्च स्तर पर पूर्व में जारी अधिसूचना के संशोधन हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।
15.	11.8	आयोग की यह भी अनुशंसा है कि पंचायत शब्द के उपयोग से होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए 'नगर पंचायत' का नाम 'नगर परिषद' किया जाए	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	सहमत है विचारण में लिया जा सकता है, पूर्व में प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् छ.ग. न.पा. अधिनियम 1961 में संशोधन हेतु विधि विभाग से परिमार्जन पश्चात् वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, इसके पश्चात् आगामी कार्यवाही नहीं की गयी।
16.	11.19	नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासन में अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आयोग की अनुशंसा है कि राज्य शासन इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त एवं कुशल कर्मियों की व्यवस्था करे।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	विभाग के अधिकारियों को छ.ग. प्रशासन अकादमी ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा क्षेत्रीय पर्यावरण एवं अध्ययन केन्द्र लखनऊ, आ.ई. एल.एस.जी.डी. एवं आस्की हैदराबाद सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है साथ ही एक्सपोजर दूर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों को भेजा जाता है। व्यापम और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जाती है।

17.	11.20	आयोग की यह अनुशंसा है कि वर्तमान संवर्ग को व्यवस्थित किया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां नये संवर्ग का गठन किया जाए यथा-लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग एवं नगरीय नियोजन जिससे नगरीय प्रशासन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	विभाग में राज्य नगर पालिका सेवा (कार्यपालन), राज्य नगर पालिका सेवा (यांत्रिकी) और राज्य नगर पालिका सेवा (स्वास्थ्य) का गठन है। नगर निवेशक का पद नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। सहायक नगर निवेशक का पद सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। लेखा, राजस्व, पर्यावरण संवर्ग के गठन हेतु विचार किया जायेगा।
18.	11.21	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 11 मई 2011 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 जारी किया गया है, परन्तु अब तक यह कार्यशील नहीं हो सका है। आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग को कार्यशील किया जावे।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु कलेक्टर गाइड लाईन के अनुसार करने के लिए नवीन नियम 2021 में प्रभावशील किया गया है पहले भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर किया जाता था।
19.	12.17	आयोग का यह अवलोकन है कि तेजी से विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ के नगर जैसे - रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में बहुमंजलीय इमारतों की भारी कमी है। ऊँची लागत की भूमि का उचित आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्नत अधोसंरचना, सेवा प्रदाय करना, सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण तंत्र की कार्यक्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक होगा। आयोग की यह अनुशंसा है कि सभी बड़े शहरों में कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) सम्पूर्ण प्रयोजनों हेतु बढ़ाया जाना चाहिए।	आवास एवं पर्यावरण विभाग के अभिमत से सहमत। अनुशंसा मान्य किया गया है।	नगरीय प्रशासन विभाग	नगरीय निकायों में बहुमंजिला इमारतों एवं कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) के लिए नगर तथा ग्राम निवेश के मापदण्डों (भूमि विकास नियम) के अनुसार अनुज्ञा दी जाती है।

20.	13.6	शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक पूजा स्थल या सार्वजनिक परोपकारी, विधवा या अवयस्क या निःशतृजन, मानसिक रूप से अक्षम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना के सदस्य एवं उनकी विधवाएं, दृष्टिहीन, परित्यक्त महिलाएं एवं मानसिक रूप से असंतुलित, छत्तीसगढ़, विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये खम्भे और ऐसे अन्य मामले जिनमें राज्य शासन ने छूट देने का निर्णय लिया हो, को कर से छूट प्राप्त है। कुछ प्रकरणों में यह छूट शर्तों के साथ है।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	अधिनियम में प्रावधानित छूट तर्कसंगत है।
21.	13.10	आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई. ऐप स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रणाली नगर पालिका निगमों में लागू की जा सकती है कालांतर में इसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में भी लागू किया जा सकता है।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा क्रमशः प्रभावशील करने की सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	65 निकायों में ऑनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। पेमेंट गेटवे द्वारा भुगतान लिया जाता है, शेष निकायों में भी की जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
22.	13.10	आयोग अनुशंसा करता है कि समय पर और अग्रिम सम्पत्ति कर का भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसका विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इससे प्रभावी एवं अधिक कर राजस्व की वसूली संभव हो सकेगी।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर विचार करने की सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	नगर पालिका निगमों में यह व्यवस्था लागू है, छ.ग. नगर पालिका निगम अधिनियम 1966 की धारा 137 में निगमों को संपत्तिकर में छूट बाबत अधिकार दिये गये हैं।
23.	13.16	आयोग यह अनुशंसा करता है कि अधिकतम दोहन की संभावना वाले बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में विज्ञापन/हॉर्डिंग कर का उपयोग राजस्व बढ़ाने में किया जाए। नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर लगाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किया जाए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	प्रदेश में हॉर्डिंग पॉलिसी लागू है, उपविधि को अंगीकृत कर सकते हैं। विज्ञापन कर का पृथक से प्रावधान नहीं है। हॉर्डिंग पॉलिसी में विज्ञापन फीस सम्मिलित है।

24.	13.29	आयोग यह अनुशंसा करता है कि स्थानीय नगरीय निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी ऋण पात्रता की सीमा मालूम हो तथा वे वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए योग्य बन सकें।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	9 अमृत शहरों के लिये वर्ष 2016-17 में इकरा (Intional Information and Credit Rating Agency) से क्रेडिट रेटिंग कराई गई थी।
25.	13.31	आयोग अनुशंसा करता है कि पर्याप्त संख्या में लेखापालों की पदस्थापना सभी नगरीय स्थानीय निकायों में की जाए और एक निश्चित समय-सीमा में अधिकारियों की आंतरिक क्षमता का विकास किया जाए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	व्यापम के माध्यम से 84 लेखापाल की भर्ती की गई है तथा पुनः रिक्त 50 लेखापाल भर्ती के लिए सहमति ली गई है।
26.	13.32	आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों का स्कंध लेने के लिए एकबार ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक मानक प्रारूप बनाया जा सके। इस प्रारूप में संपत्तियों की भौतिक स्थिति, संख्यांक और उनका पूरा विवरण सम्मिलित होगा। इसके संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे ऐसे स्कंधों का अभिलेखीकरण एवं व्यवस्थापन का कार्य प्रत्येक नगरीय निकाय में निश्चित समयावधि में अद्यतन किया जा सके। ऐसे अभिलेख को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	सहमत निरंतर अद्यतन कराया जा रहा है।
27.	13.36	आयोग यह अनुशंसा करता है कि भूमि से हो सकने वाली आय यथा-परिवर्तन (व्यपवर्तन) शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि के स्रोत का विवरण दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाए। कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) पर एक निर्धारित सीमा के ऊपर शुल्क आदि का निर्धारण संपूर्ण योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये इसे एक पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे भूमि मूल्यांकन आधारित स्रोत का शहरी अधोसंरचना की परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	भूमि से हो सकने वाली आय यथा परिवर्तन शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि से संबंधित विषय नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित है। विभाग समन्वय के अनुशंसा पर कार्यवाही हेतु सहमत है।

28.	13.40	आयोग यह अनुशंसा करता है कि वार्ड एवं मोहल्ला समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी समितियाँ जिन्होंने सम्पत्ति कर की चालू मांग के 90 प्रतिशत तक वसूली में योगदान दिया हो के लिए उस राशि का 20 से 25 प्रतिशत तक सुरक्षित रखा जाये। यह राशि इन मोहल्ला समितियों द्वारा सुझाये गये अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। नागरिक समुदायों में इससे सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा न सिर्फ आय के साधनों को गतिशील बनाने में वस्त्र विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। आयोग का यह मत है कि इससे सक्रिय भागीदारी की संस्कृति पैदा होगी जो दीर्घकाल में सतत विकास में सहायक होगी।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	
29.	15.7	आयोग की अनुशंसा है कि संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का अभिलेखीकरण एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उनका अंगीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	
30.	16.4	आयोग की अनुशंसा है कि चरणबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों के सभी कार्यक्षेत्रों में ई-गवर्नेंस का उपयोग अविलंब प्रारंभ किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को ई-गवर्नेंस में प्रशिक्षित किया जाए। जिससे प्रभावी डाटा प्रबंधन, योजना और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी तथा नागरिकों के साथ बेहतर अंतर्संबंध स्थापित होंगे, जो प्रभावी सामुदायिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।	चरणबद्ध तरीके से ई-गवर्नेंस की प्रणाली कर उपयोग प्रारंभ करने की सहमति दी गई है।	नगरीय प्रशासन विभाग	
31.	16.7	आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं में संचालित सभी केन्द्रीय एवं राज्य शासन की योजनाओं में सामाजिक अंश प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। अंश प्रतियोगिता जिला पंचायत की वेबसाइट के माध्यम से जनसुलभ होना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा से सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	

32.	16.8	आयोग की अनुशंसा है कि सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एकीकृत जिला विकास योजना बनाई जानी चाहिए और इसे राज्य की विकास योजना के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छ.ग. न.पा.नि. अधिनियम की धारा 67 तथा न.पा. अधिनियम की धारा 124 'ख' में जिला विकास योजना तथा वार्षिक योजना बनाने हेतु प्रावधान है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पत्र दिनांक 28/12/2021 एकीकृत जिला विकास योजना तथा पत्र दिनांक 08/11/2021 के द्वारा वार्षिक - योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं।
	16.9	यह आयोग पूर्व के आयोगों की अनुशंसा को दोहराता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्ड समितियों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए।		नगरीय प्रशासन विभाग	
33.	16.10	आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय स्थानीय निकायों को अधोसंरचना विकसित करने और आय अर्जित करने वाली योजनाओं के लिए भविष्य में उपलब्ध कराई जा सकने वाली रिवत भूमि को विन्हाकित, सूचीबद्ध एवं दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन द्वारा एक भूमि बैंक बनाया जाना चाहिए जिससे भूमि की मांग आने पर स्थानीय निकायों को भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जा सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	राजस्व विभाग	
34.	16.11	आयोग अनुशंसा करता है कि सामान्यतः अंतरिम अनुमानों से बचने के लिये उचित समय पर, अगले वित्त आयोग की अधिनियम अवधि के प्रारंभ होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिये।	तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को आयोग के निर्देश पद (टीओआर) में निधारित अवधि 2017-18 से 2021-22 के स्थान पर अवधि 2020-21 से आगामी पांच वर्षों के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिपोर्टों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनियम अवधि (2017-18 से 2021-22) में से वर्ष 2017-18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यन्वित हो चुका है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	आयोग की अनुशंसा है कि अधिनियम अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 में पंचायती राज संस्थाओं लिए 6.91 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किये जाने का अनुशंसा है जो वर्तमान में अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किया जाना चाहिए।
	16.12	आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ ही वित्त विभाग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ में कार्यरत वर्ग 2, 3 और 4 कर्मचारियों को राज्य वित्त आयोग कार्यालय में संलग्न किया जाना चाहिये।	अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। साथ ही यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनियम अवधि 2012-17 के लिये राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है।	वित्त विभाग	

36.	17.18	तृतीय राज्य वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है, कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को दिए जाए।	तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को निम्नलिखित पद (टीओआर) में निर्धारित अवधि 2017-18 से 2021-22 के स्थान पर अवधि 2020-21 से आगामी पांच वर्षों के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिपोर्टों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनिर्णय अवधि (2017-18 से 2021-22) में से वर्ष 2017-18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यान्वित हो चुका है। अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। साथ ही यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2012-17 के लिये राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है।	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	नगरीय निकायों को वर्तमान में राज्य के शुद्ध कर से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 1.85 प्रतिशत उपलब्ध कराया जा रहा है। तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को आबंटन प्रदाय किया जाए।
37.	17.19	आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए क्रमशः 6.91 प्रतिशत एवं 2.09 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किया जाए।	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को यदि 9 प्रतिशत शुद्ध कर का भुगतान किया जाता है तो नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाले 2.09 प्रतिशत का आबंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 से किया जाना उचित होगा।	

अनुलग्नक - 6.1

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या				
क्र.	जिले का नाम	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या		
		जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	रायपुर	1	4	416
2	महासमुन्द	1	5	551
3	धमतरी	1	4	370
4	दुर्ग	1	3	304
5	राजनांदगांव	1	9	814
6	कबीरधाम	1	4	468
7	बस्तर	1	7	433
8	नारायणपुर	1	2	104
9	दंतेवाड़ा	1	4	143
10	बीजापुर	1	4	170
11	कांकेर	1	7	454
12	बिलासपुर	1	4	483
13	गौरेला — पेण्ड्रा — मरवाही	1	3	166
14	कोरबा	1	5	412
15	जांजगीर—चांपा	1	9	657
16	रायगढ़	1	9	774
17	सरगुजा	1	7	439
18	जशपुर	1	8	444
19	कोरिया	1	5	363
20	बलौदाबजार	1	6	644
21	गरियाबंद	1	5	336
22	बेमेतरा	1	4	429
23	बालोद	1	5	435
24	मुंगेली	1	3	370
25	कोंडागांव	1	5	383
26	सुकमा	1	3	153
27	सूरजपुर	1	6	481
28	बलरामपुर	1	6	468
योग		28	146	11664

स्रोत :- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 6.2

2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जिला पंचायतों की औसत जनसंख्या		
क्र.	जिला पंचायत	जनसंख्या
1	धमतरी	661882
2	बीजापुर	213558
3	बालोद	722569
4	बेमेतरा	721192
5	बलरामपुर — रामानुजगंज	695808
6	बलौदाबजार — भाटापारा	1298534
7	कबीरधाम	730267
8	कांकेर	682135
9	कोंडागांव	530512
10	कोरिया	478150
11	कोरबा	723121
12	महासमुन्द	913614
13	मुंगेली	641468
14	बिलासपुर	1002797
15	रायपुर	860687
16	झयग	1219077
17	राजनांदगांव	1264614
18	सरगुजा	703424
19	सुकमा	242718
20	सूरजपुर	710753
21	दुर्ग	607015
22	दंतेवाड़ा	221274
23	जांजगीर—चांपा	1394646
24	जशपुर	780263
25	नारायणपुर	116962
26	गरियाबंद	557199
27	गौरेला — पेण्ड्रा — मरवाही	304135
28	बस्तर	611189
योग		1,96,09,563

स्रोत :- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य की जिलेवार अनुसूचित (पेसा) जनपद/ग्राम पंचायत की जानकारी

क्र.	क्षेत्र	जिले का नाम	कुल जनपद पंचायत	पेसा जनपद पंचायत	पेसा ग्राम पंचायत	जनपद पंचायतवार पेसा ग्राम पंचायतों की संख्या									
1		नारायणपुर	2	2	104	नारायणपुर - 68	ओरछा - 36								
2		सुकमा	3	3	153	सुकमा - 33	छिन्दवाड़ - 59	कोन्टा - 61							
3		दत्तेवाड़ा	4	4	143	दत्तेवाड़ा - 38	गीरम - 46	कटेकर्याण - 26	कुआकोण्डा - 33						
4		बीजापुर	4	4	170	बीजापुर - 36	भैरमगढ़ - 60	मोपालपट्टनम - 35	उसूर - 39						
5		कोण्डागांव	5	5	383	कोण्डागांव - 125	वडेरजपुर - 49	माकडी - 87	केशकाल - 69	फरसगांव - 73					
6	सम्पूर्ण	कोरबा	6	5	412	कोरबा - 74	करतला - 78	कटघोरा - 53	पाली - 93	पोडी उपरोडा - 114					
7	अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला	कोरिया	5	5	363	बैकुण्ठपुर - 88	सोनहल - 42	खडगवां - 77	मनेन्द्रगढ़ - 72	मरतपुर - 84					
8		सूरजपुर	6	6	481	सूरजपुर - 108	भैरमगढ़ - 78	ओडगी - 74	रामानुजनगर - 74	प्रेमनगर - 46	प्रतापपुर - 101				
9		बलरामपुर	6	6	468	बलरामपुर - 75	रामचन्द्रपुर - 91	वाङ्गफनगर - 95	शंकरगढ़ - 60	कुसमी - 77	राजपुर - 70				
10		बस्तर	7	7	433	बस्तर - 88	बास्तानगर - 34	लोहणडीगुडा - 49	बकावण्ड - 93	जगदलपुर - 71	तोकपाल - 82				
11		कोकर	7	7	454	कोकर - 64	कोयलीवेडा - 103	अन्तागढ़ - 56	चासमा - 64	मानुप्रतापपुर - 52	नरहरपुर - 71	दुर्गकोन्दल - 44			
12		सरगुजा	7	7	439	अम्बिकापुर - 101	लखनपुर - 74	उदयपुर - 59	लुण्डा - 77	बतौली - 42	मैनपाट - 44	सीतापुर - 42			
13		जशपुर	8	8	444	जशपुर - 44	कांसाबेल - 40	बनीचा - 93	फरसाबहार - 58	कुनकुरी - 51	दुलदुला - 30	पल्लगांव - 84	मनोरा - 44		
14		गो.पे.मा.	3	3	166	मरवाही - 74	पेण्डा - 41	गोरिला - 51							
15		बलोद	5	1	60	डौणडी - 60									
16	अशिक	धमतरी	4	1	102	नगरी - 102									
17	अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला	बिलासपुर	4	0	85	कोटा - 85									
18		गरियाबंद	5	3	210	गरियाबंद - 62	मैनपुर - 74	छुरा - 74							
19		राजनांदगांव	9	3	185	मोहला - 57	मानपुर - 59	चौकी - 69							
20		रायगढ़	9	5	377	खरसिया - 81	धरघोडा - 42	धरघोडा - 42	तमनार - 61	लैलूगा - 75	धरमजयगढ़ - 118				
योग			108	85	5632										

स्रोत :- पंचायत राज एवं ग्रामाण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

**जिला स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या
(01.07.2022 की स्थिति में)**

क्र.	जिले का नाम	नगरीय निकायों की संख्या			
		नगर पालिक निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	योग
1	रायपुर	2	3	7	12
2	बलौदाबाजार	0	2	5	7
3	गरियाबंद	0	1	3	4
4	धमतरी	1	0	5	6
5	महासमुंद	0	3	3	6
6	दुर्ग	4	4	3	11
7	बालो	0	2	6	8
8	राजनांदगांव	1	1	2	4
9	बस्तर	1	0	1	2
10	बिलासपुर	1	2	4	7
11	कोरबा	1	2	2	5
12	रायगढ़	1	1	5	7
13	सरगुजा	1	0	2	3
14	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1	1	3	5
15	बेमेतरा	0	1	7	8
16	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0	1	2	3
17	कवर्धा	0	1	5	6
18	कोण्डागांव	0	1	2	3
19	नारायणपुर	0	1	0	1
20	कांकेर	0	1	5	6
21	दंतेवाड़ा	0	3	2	5
22	सुकमा	0	1	2	3
23	बीजापुर	0	1	2	3
24	मुंगेली	0	1	3	4
25	जांजगीर	0	3	6	9
26	सक्ती	0	1	5	6
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	1	4	5
28	जशपुर	0	1	4	5
29	बलरामपुर	0	1	4	5
30	सूरजपुर	0	1	5	6
31	कोरिया	0	2	0	2
32	मोहला-मानपुर-चौकी	0	0	1	1
33	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	2	2
	योग	14	44	112	170

स्रोत :- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

जनगणना 2011 के अनुसार नगर निगम की जनसंख्या

क्र.	जिले का नाम	नगर पालिक निगम	जनसंख्या
1	रायपुर	रायपुर	1048120
2		बीरगांव	96294
3	धमतरी	धमतरी	89860
4	दुर्ग	दुर्ग	267465
5		भिलाई	516862
6		रिसाली	108838
7		भिलाईचरोदा	98008
8	राजनांदगांव	राजनांदगांव	163114
9	बस्तर	जगदलपुर	125463
10	बिलासपुर	बिलासपुर	514144
11	कोरबा	कोरबा	363390
12	रायगढ़	रायगढ़	166034
13	सरगुजा	अंबिकापुर	125392
14	मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर	चिरमिरी	85317
	योग		37,68,301

स्रोत :- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी

जनगणना 2011 के अनुसार नगर पालिका परिषद की जनसंख्या

क्र.	जिले का नाम	नगर पालिक परिषद	जनसंख्या
1	रायपुर	तिल्दानेवरा	32331
2		गोबरानवापारा	29315
3		आरंग	19091
4	गरियाबंद	गरियाबंद	10426
5	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	26632
6		भाटापारा	57512
7	महासमुंद	महासमुंद	54413
8		बागबाहरा	19529
9		सरायपाली	20043
10	दुर्ग	जामुल	25878
11		कुम्हारी	35054
12		अहिवारा	20384
13		अमलेश्वर	10489
14	बालोद	बालोद	23648
15		दल्लीराजहरा	44363
16	बेमेतरा	बेमेतरा	28536
17	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	37372
18	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	22564
19	कवर्धा	कवर्धा	44205
20	कोण्डागांव	कोण्डागांव	30921
21	नारायणपुर	नारायणपुर	22106
22	कांकर	कांकर	27541
23	दंतेवाड़ा	किरन्दुल	18887
24		बड़ी बचेली	21435
25		दन्तेवाड़ा	13633
26	सुकमा	सुकमा	13926
27	बीजापुर	बीजापुर	16129
28	बिलासपुर	तखतपुर	19968
29		रतनपुर	24636
30	मुंगेली	मुंगेली	31250
31	कोरबा	दीपका	27158
32		कटघोरा	22690
33	जांजगीर	जांजगीर-नैला	40561
34		चांपा	45256
35		अकलतरा	22712
36	सक्ती	सक्ती	21955
37	रायगढ़	खरसिया	18939
38	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़	24798
39	जशपुर	जशपुरनगर	25422
40	बलरामपुर	बलरामपुर	4456
41	सूरजपुर	सूरजपुर	20189
42	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	33071
43	कोरिया	बैकुण्ठपुर	29182
44		शिवपुरचरचा	23514
	योग		11,62,120

स्रोत :- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 6.7

जनगणना 2011 के अनुसार नगर पंचायत की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार नगर पंचायत की जनसंख्या							
क्र.	जिले का नाम	नगर पंचायत का नाम	जनसंख्या	क्र.	जिले का नाम	नगर पंचायत का नाम	जनसंख्या
1	रायपुर	अभनपुर	14432	57	दत्तेवाड़ा	नरहरपुर	4509
2		खरोरा	9236	58		गौदम	7440
3		माना कैम्प	11953	59	सुकमा	बारसूर	6636
4		कुरा	8857	60		दोरनापाल	7238
5		मंदिरहसौद	16086	61	बीजापुर	कोण्टा	6882
6		समोदा	6907	62		भैरमगढ़	9026
7	गरियाबंद	चंदखुरी	3341	63	बिलासपुर	भोपालपट्टनम	4445
8		राजिम	14092	64		कोटा	18405
9		फिंगेश्वर	9752	65		बोदरी	17481
10		छुरा	6079	66		बिल्हा	11048
11	बलौदाबाजार	सिमगा	16027	67	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही मुंगेली	मल्हार	8505
12		लवन	8984	68		गौरिला	18165
13		कसडोल	14071	69		पेण्ड्रा	14120
14		पलारी	8567	70		लोरमी	15156
15	धमतरी	टुण्डरा	8211	71	कोरबा	पथरिया	6349
16		कुरुद	13783	72		सरगांव	7484
17		मगरलोड	6280	73	पाली	5514	
18		नगरी	13308	74	छुरीकला	8239	
19		भखारा	7547	75	जांजगीर	बलौदा	13630
20		आमदी	6600	76		खरौद	10193
21	महासमुंद	पिथौरा	8428	77	सक्ती	शिवरीनारायण	9714
22		बसना	10345	78		सारागांव	7225
23	तुमगांव	7394	79	नवागढ़		8118	
24	दुर्ग	धमधा	9961	80		राहौद	6160
25		पाटन	10133	81	रायगढ़	नया बाराद्वार	8840
26	उतई	8752	82	अडभार		7272	
27	बालोद	गुण्डरदेही	8614	83	रायगढ़	जैजपुर	7946
28		डौडी	8042	84		डभरा	7854
29		डौंडीलोहारा	6045	85		चन्द्रपुर	7688
30		गुरु	3775	86		धर्मजयगढ़	14354
31	बेमेतरा	अर्जुन्दा	4851	87	सारंगढ़ बिलाईगढ़	घरघोड़ा	9455
32		चिखलाकसा	6160	88		लैलुंगा	8208
33		थानखम्हरिया	8373	89		पुसौर	4744
34		साजा	5257	90		किरोडीमलनगर	13102
35	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	देवकर	6358	91	जशपुर	सरिया	6927
36		बेरला	5165	92		बरमकेला	5600
37		परपोड़ी	3741	93		बिलाईगढ़	5544
38		नवागढ़	10541	94		भटगांव	10371
39	मोहला मानपुर चौकी	मारो	6596	95	सरगुजा	पत्थलगंव	16613
40		गण्डई	13278	96		कोतबा	6805
41	राजनांदगांव	छुईखदान	7093	97	बलरामपुर	बगीचा	10427
42		अम्बागढ़चौकी	9889	98		कुनकुरी	13846
43	कवर्धा	डोंगरगांव	14693	99	सूजरपुर	सीतापुर	9361
44		छुरिया	4509	100		लखनपुर	6270
45	बस्तार	पंडरिया	16165	101	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	रामानुजगंज	11893
46		बोड़ला	5689	102		कुसमी	7447
47		पाण्डातराई	7008	103		राजपुर	4838
48		सहसपुर लोहारा	7017	104		वाड्डफनगर	6048
49	कांकर	पिपरिया	4859	105	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	विश्रामपुर	11367
50		बस्तार	10174	106		प्रतापपुर	5635
51	कोण्डागांव	केशकाल	10779	107	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	भटगांव	11204
52		फरसगांव	6306	108		जरही	7228
53	कांकर	भानुप्रतापपुर	8125	109	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	प्रेमनगर	4954
54		चारामा	9707	110		झगराखण्ड	7680
55	कांकर	परखाजूर	10201	111	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	खोंगापानी	17400
56		अंतागढ़	6777	112		नई लेदरी	5333
			योग				10,08,849

स्रोत :- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार										
क्र.	जिला	ग्राम पंचायतें			गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतें			अनुसूचित ग्राम पंचायतें		
		कुल	सैंपल (प्रतिदर्श)	प्रतिशत	कुल	सैंपल (प्रतिदर्श)	प्रतिशत	कुल	सैंपल (प्रतिदर्श)	प्रतिशत
1	बस्तर	433	132	30.48	—	—	—	433	132	30.48
2	बिलासपुर	483	145	30.02	398	145	36.4	85	—	—
3	दत्तेवाड़ा	143	83	58.04	—	—	—	143	83	58.04
4	धमतरी	370	234	63.24	268	175	65.30	102	59	57.84
5	दुर्ग	304	160	52.63	304	160	52.63	—	—	—
6	जाजगीर—चांपा	657	378	57.53	657	378	57.53	—	—	—
7	जशपुर	444	204	45.95	—	—	—	444	204	45.95
8	कांकेर	454	138	30.40	—	—	—	454	138	30.40
9	कबीरधाम	468	332	70.94	468	332	70.94	—	—	—
10	कोरबा	412	176	42.72	—	—	—	412	176	42.72
11	कोरिया	363	169	46.56	—	—	—	363	169	46.56
12	महासमुन्द	551	312	56.62	551	312	56.62	—	—	—
13	रायगढ़	774	511	66.02	397	294	74.06	377	217	57.56
14	रायपुर	416	206	49.52	416	206	49.52	—	—	—
15	राजनांदगांव	814	408	50.12	629	302	48.01	185	106	57.30
16	सरगुजा	439	251	57.15	—	—	—	439	251	57.18
17	बीजापुर	170	92	54.12	—	—	—	170	92	57.12
18	नारायणपुर	104	86	82.69	—	—	—	104	86	82.69
19	सुकमा	153	48	31.37	—	—	—	153	48	31.37
20	कोडारगाँव	383	163	42.56	—	—	—	383	163	42.56
21	बलौदाबाजार	644	290	45.03	644	290	45.03	—	—	—
22	गरियाबंद	336	100	29.76	126	38	30.16	210	62	29.52
23	बालोद	435	370	85.06	375	319	85.07	60	51	85.00
24	मुंगेली	370	202	54.59	370	202	54.59	—	—	—
25	सूरजपुर	481	279	58.00	—	—	—	481	279	58.00
26	बलरामपुर	468	219	46.79	—	—	—	468	219	46.79
27	बेमेतरा	429	162	37.76	429	162	37.76	—	—	—
28	गौरेला—पेण्ड्रा— मरवाही	166	100	60.24	—	—	—	166	100	60.24
योग		11664	5950	51.01	6032	3315	54.95	5632	2635	46.78

स्रोत :- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता

क्र.	जिला	राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति		गैर-अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति		अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति	
		शौचालय वाले घरों की प्रतिशतता	ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत	शौचालय वाले घरों की प्रतिशतता	ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत	शौचालय वाले घरों की प्रतिशतता	ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत
1	बस्तर	94.13	79.55	—	—	94.13	79.55
2	बिलासपुर	87.13	73.10	87.09	73.10	—	—
3	दंतेवाड़ा	65.36	96.39	—	—	65.36	96.39
4	धमतरी	94.58	97.44	93.33	98.29	98.82	94.92
5	दुर्ग	97.06	98.13	97.06	98.13	—	—
6	जांजगीर-चांपा	50.96	65.34	50.96	65.34	—	—
7	जशपुर	98.67	92.16	—	—	98.67	92.16
8	कांकेर	94.23	81.88	—	—	94.23	81.88
9	कबीरधाम	88.31	78.61	88.31	78.61	—	—
10	कोरबा	90.38	78.98	—	—	90.38	78.98
11	कोरिया	89.29	68.64	—	—	89.29	68.64
12	महासमुन्द	96.45	79.49	96.45	79.49	—	—
13	रायगढ़	86.25	68.30	84.68	59.86	88.40	79.72
14	रायपुर	94.30	74.27	94.30	74.27	—	—
15	राजनांदगांव	96.68	80.39	96.39	80.13	97.54	81.13
16	सरगुजा	89.70	89.24	—	—	89.70	89.24
17	बीजापुर	41.06	52.17	—	—	41.06	52.17
18	नारायणपुर	72.54	79.07	—	—	72.54	79.07
19	सुकमा	55.49	81.25	—	—	55.49	81.25
20	कोंडागाँव	94.46	65.64	—	—	94.46	65.64
21	बलौदाबाजार	88.02	86.90	88.02	92	—	—
22	गरियाबंद	92.92	89.00	93.47	97.37	92.53	83.87
23	बालोद	95.44	73.51	95.26	71.79	96.60	84.31
24	मुंगेली	83.43	78.71	83.43	78.71	—	—
25	सूरजपुर	94.46	82.80	—	—	94.46	82.80
26	बलरामपुर	88.66	58.45	—	—	88.66	58.45
27	बेमेतरा	93.20	81.48	93.20	81.48	—	—
28	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	86.73	87.00	—	—	86.73	87.00
योग		85.02	78.22	82.63	77.56	88.82	79.05

स्रोत :- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति

अनुलग्नक - 7.3

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

क्र.	जिला	राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति			गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति			अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति																																																																																																																																																																			
		नल जल वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	नल जल योजना है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत

स्रोत :- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

जल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मापदंड

क्र.	विशेषता	इकाई	अपेक्षा (स्वीकार्य सीमा)	वैकल्पिक स्रोत की अनुपस्थिति में अनुमेय सीमा
1	पी.एच. मान	—	6.5–8.5	कोई ढील नहीं
2	पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ	मिलीग्राम/लीटर	500	2000
3	गंदगी	एनटीयू	1	5
4	क्लोराईड	मिलीग्राम/लीटर	250	1000
5	पूर्ण क्षारीयता	मिलीग्राम/लीटर	200	600
6	पूर्ण खारापन	मिलीग्राम/लीटर	200	600
7	सल्फेट	मिलीग्राम/लीटर	200	400
8	आयरन	मिलीग्राम/लीटर	1.0	कोई ढील नहीं
9	पूर्ण आर्सेनिक	मिलीग्राम/लीटर	0.01	कोई ढील नहीं
10	फ्लोराईड	मिलीग्राम/लीटर	1.0	1.5
11	नाइट्रेट	मिलीग्राम/लीटर	45	कोई ढील नहीं
12	पूर्ण कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में पता लगने योग्य नहीं होना चाहिए।		

स्रोत – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी

जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति

क्र.	जिला	(01 / 04 / 2023) तक कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या	(01 / 04 / 2023) तक PWS में घरेलु कनेक्शन परिवारों की संख्या	(24 / 08 / 2023) तक रिपोर्ट किए गए कुल घरेलु कनेक्शन	(24 / 08 / 2023) तक रिपोर्ट किए गए PWS के साथ कुल घरेलु कनेक्शन का प्रतिशत
1	सारंगढ़-बिलाईगढ़	162580	32411	62554	38.48
2	जशपुर	212778	60063	89017	41.84
3	कोरबा	206953	56060	88296	42.66
4	बलरामपुर	197552	55766	90039	45.58
5	सुकमा	66312	20426	30646	46.21
6	सरगुजा	185930	54632	87208	46.9
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	84537	24297	39842	47.13
8	बीजापुर	56225	21356	26620	47.35
9	मोहला-मानपुर-चौकी	64593	23385	31044	48.06
10	कांकेर	151065	60095	74328	49.2
11	सूरजपुर	164515	53419	81268	49.4
12	बस्तर	169463	57977	84928	50.12
13	बिलासपुर	246673	91653	125583	50.91
14	दंतेवाड़ा	50732	19582	25880	51.01
15	भरतपुर-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी	83350	29471	44204	53.03
16	रायगढ़	242821	99815	129404	53.29
17	बलौदाबाजार	231664	87992	124347	53.68
18	कोरिया	51910	22187	28461	54.83
19	नारायणपुर	30331	13062	17832	58.79
20	गरियाबंद	153558	70101	90991	59.26
21	महासमुन्द	239342	96615	141915	59.29
22	कोंडागाँव	125593	50260	77791	61.94
23	कबीरधाम	199294	99551	125048	62.75
24	बेमेतरा	177440	90051	114603	64.59
25	बालोद	176182	80935	114696	65.1
26	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	74169	35892	49393	66.6
27	सक्ति	156663	77959	107790	68.8
28	जांजगीर-चांपा	207156	103695	143921	69.47
29	मुंगेली	166869	81004	118274	70.88
30	राजनांदगांव	156789	92936	113815	72.59
31	दुर्ग	155801	89339	117233	75.25
32	रायपुर	190001	124801	143947	75.76
33	धमतरी	153734	115339	131807	85.74
योग		4992575	2092127	2872725	57.54

स्रोत :- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के साथ समीक्षा बैठक से प्राप्त जानकारी।

(दिनांक 25 अगस्त 2023)

अनुलग्नक - 7.6

ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट निराकरण

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

क्र.	जिला	राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति		गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति		अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति	
		जल निकासी (नाली) की व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहाँ घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है।	जल निकासी (नाली) की व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहाँ घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है।	जल निकासी (नाली) की व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहाँ घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है।
1	बस्तर	6.06	19.7	—	—	65.9	19.7
2	बिलासपुर	67.6	40.7	67.6	40.7	—	—
3	दंतेवाड़ा	31.3	19.3	—	—	31.3	19.3
4	धमतरी	73.9	35.9	82.9	41.1	47.5	20.3
5	दुर्ग	85.6	57.5	85.6	57.5	—	—
6	जांजगीर-चांपा	65.1	21.4	65.1	21.4	—	—
7	जशपुर	68.1	32.8	—	—	68.1	32.8
8	कांकेर	44.9	33.3	—	—	44.9	33.3
9	कबीरधाम	13.5	25	61.1	25	—	—
10	कोरबा	59.7	29.5	—	—	59.7	29.5
11	कोरिया	27.2	23.1	—	—	27.2	23.1
12	महासमुन्द	57	19.5	57	19.5	—	—
13	रायगढ़	66.3	34	71.8	34	59	34.1
14	रायपुर	69.5	36.4	79.1	36.4	—	—
15	राजनांदगांव	72.8	18.9	74.5	17.5	67.9	22.6
16	सरगुजा	61	12.3	—	—	61	12.3
17	बीजापुर	6.5	4.3	—	—	6.5	4.3
18	नारायणपुर	13.9	32.6	—	—	20.9	32.6
19	सुकमा	16.7	14.6	—	—	16.7	14.6
20	कोडार्गाँव	19.6	9.8	—	91 ^७	19.6	9.8
21	बलौदाबाजार	51	34.8	51	34.8	—	—
22	गरियाबंद	56	22	17.0	18.4	45.2	24.2
23	बालोद	72.7	26.5	73.7	24.4	66.7	39.2
24	मुंगेली	58.9	15.8	58.9	15.8	—	—
25	सूरजपुर	43.7	22.2	—	—	43.7	22.2
26	बलरामपुर	34.2	26.9	—	—	34.2	26.9
27	बेमेतरा	59.3	22.8	59.3	22.8	—	—
28	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	48	22	—	—	48	22
योग		58	26.1	67.3	28.1	46.2	23.5

स्रोत - चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट योजना की स्थिति

अनुलग्नक - 7.7

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

क्र.	जिला	राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति					गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति					अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति							
		स्ट्रीट लाइट है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	स्ट्रीट लाइट है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	सुधार राशि का अनुप लब्धता	एक से अधिक कारण	एक से अधिक कारण	स्ट्रीट लाइट है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	स्ट्रीट लाइट है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	सुधार राशि का अनुप लब्धता	एक से अधिक कारण	एक से अधिक कारण	स्ट्रीट लाइट है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	स्ट्रीट लाइट है, पर चालू नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	सुधार राशि का अनुप लब्धता	एक से अधिक कारण	एक से अधिक कारण			
1	बस्तर	56.1	23.5	3.2	74.2	16.1	6.4	-	-	-	-	56.1	23.5	3.2	74.2	16.1	6.4		
2	बिलासपुर	26.2	29	19	64.3	14.3	2.4	26.2	29	19	64.3	14.3	2.4	-	-	-	-		
3	देवड़ा	10.8	67.5	3.6	5.4	85.7	5.4	-	-	-	-	10.8	67.6	3.6	5.4	85.7	5.4		
4	धमतरी	77.3	4.3	0	30	40	30	82.9	1.7	0	0	66.7	33.3	61	11.9	0	42.8	28.6	
5	दुर्ग	91.9	1.9	0	66.7	33.3	0	91.9	1.9	0	66.7	33.3	0	-	-	-	-		
6	जाजगीर-चापा	57.9	16.4	6.4	22.6	33.9	37.1	57.9	16.4	6.4	22.6	33.9	37.1	-	-	-	-		
7	जशपुर	33.3	24	18.4	46.9	26.5	8.2	-	-	-	-	33.3	24	18.4	46.9	26.5	8.2		
8	कोकर	13.5	12.3	11.8	47.1	41.2	0	-	-	-	-	37	12.3	11.8	47.1	41.2	0		
9	कबीरधाम	21.4	32.5	10.2	25.9	36.1	27.8	21.4	32.5	10.2	25.9	36.1	27.8	-	-	-	-		
10	कोरबा	65.9	20.4	8.3	27.8	41.7	22.2	-	-	-	-	-	65.9	20.4	8.3	27.8	22.2		
11	कोरिया	17.7	48.5	2.4	19.5	73.2	4.9	-	-	-	-	-	17.7	48.5	2.4	19.5	73.2	4.9	
12	महासमुन्द	54.5	7	4.5	40.9	31.8	22.7	54.5	7	4.5	40.9	31.8	22.7	-	-	-	-		
13	रायगढ़	69.5	11	0	71.4	12.5	16.1	75.2	12.2	0	75	5.6	19.4	61.7	9.2	0	65	25	10
14	रायपुर	74.3	7.8	12.5	56.2	18.7	12.5	74.3	7.8	12.5	56.2	18.7	12.5	-	-	-	-		
15	राजनांदगांव	54.9	15.2	11.3	32.3	32.3	24.2	56	13.2	12.5	42.5	32.5	12.5	51.9	20.7	9.1	13.6	31.8	48.4
16	सरगुजा	49	27.5	11.6	49.3	18.8	20.3	-	-	-	-	-	49	27.5	11.6	49.3	18.8	20.3	
17	बीजापुर	13.9	28.3	3.8	11.5	53.8	30.8	-	-	-	-	-	30.4	28.3	3.8	11.5	53.8	30.8	
18	नारायणपुर	45.3	40.7	0	48.6	48.6	2.9	-	-	-	-	-	45.3	40.7	0	48.6	48.4	2.9	
19	सुकमा	31.2	25	0	91.7	8.3	0	-	-	-	-	-	31.2	25	0	81.7	8.3	0	
20	कोडगाँव	36.8	11.7	26.3	21	15.8	36.8	-	-	-	-	-	36.8	11.7	26.3	21	15.8	36.8	
21	बलौदबाजार	56.9	3.8	17.0	36.4	18.2	27.3	56.9	3.8	18.2	36.4	18.2	27.3	-	-	-	-		
22	गरियाबंद	45	15	13.3	40	40	6.7	57.9	21	12.5	50	37.5	0	37.1	11.3	14.3	28.6	42.9	14.3
23	बालोद	88.4	4.3	6.2	18.7	37.5	37.5	89.7	4.1	7.7	15.4	49.0	38.5	80.4	5.9	0	33.3	33.3	33.3
24	मुंगेली	25.7	18.3	8.1	75.7	2.7	13.5	25.7	18.3	8.1	75.7	2.7	13.5	-	-	-	-	-	-
25	सूरजपुर	31.9	50.2	5.7	40	35	19.3	-	-	-	-	-	31.9	50.2	5.7	40	33	12.3	12.3
26	बलरामपुर	16.9	56.2	32.5	48.8	10.6	8.1	-	-	-	-	-	16.9	56.2	32.5	48.6	10.6	8.1	8.1
27	बेमतरा	80.2	3.1	20	40	20	20	80.2	3.1	20	40	20	20	-	-	-	-	-	-
28	गोरेला-पेठड़ा-मरवाही	33	26.1	11.4	74.3	14.3	0	-	-	-	-	-	33	35	11.4	74.3	14.3	0	0
योग		51.2	20.1	10.6	40.9	32.4	16.1	60	12.2	9.6	42.6	26.1	21.7	40.3	29.3	11.1	40	35.6	13.2

स्रोत - चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समक

ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी तथा मितानिन

क्र.	जिला	राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति			गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति			अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति		
		जिलेवार प्रतिग्राम पंचायत आंगनबाड़ी की औसत संख्या	जिलेवार ग्राम पंचायतों में एक से अधिक आंगनबाड़ी का प्रतिशत	मितानिन की सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	जिलेवार प्रति ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी की औसत संख्या	जिलेवार ग्राम पंचायतों में एक से अधिक आंगनबाड़ी का प्रतिशत	मितानिन की सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	जिलेवार प्रति ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी की औसत संख्या	जिलेवार ग्राम पंचायतों में एक से अधिक आंगनबाड़ी का प्रतिशत	मितानिन की सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
1	बस्तर	4.5	99.2	96.2	—	—	—	4.5	99.2	96.2
2	बिलासपुर	6.1	93.8	98.6	3.0	93.8	98.6	—	—	—
3	दंतेवाड़ा	7.8	97.6	95.2	—	—	—	7.8	97.6	95.2
4	धमतरी	2.6	92.3	94.0	2.5	92	93.7	3.1	93.2	94.9
5	दुर्ग	3.0	93.7	96.9	—	—	—	—	—	—
6	जाजगीर-चांपा	2.9	90.7	97.3	2.9	90.7	97.3	—	—	—
7	जशपुर	8.7	100.0	97.1	—	—	—	8.7	100	97.1
8	कांकेर	4.2	99.3	97.8	—	—	—	4.2	99.3	97.8
9	कबीरधाम	3.5	98.2	93.7	3.5	98.2	93.7	—	—	—
10	कोरबा	13.5	100.0	99.4	—	—	—	5.6	100	99.4
11	कोरिया	4.4	97.0	95.9	—	—	—	4.4	97.0	95.9
12	महासमुन्द	4.6	96.8	96.8	4.6	96.8	96.8	—	—	—
13	रायगढ़	3.7	96.9	95.9	3.0	95.6	96.6	4.7	98.6	94.9
14	रायपुर	4.0	92.2	98.1	4.0	92.2	98.1	—	—	—
15	राजनांदगांव	69.5	97.3	95.6	3.3	96.4	99.0	4.5	100	85.5
16	सरगुजा	5.5	99.2	97.6	—	—	—	5.5	99.2	97.6
17	बीजापुर	6.0	100.0	88.0	—	—	—	6.0	100	88.0
18	नारायणपुर	4.2	93.0	83.7	—	—	—	4.2	93.0	83.7
19	सुकमा	13.9	100.0	95.8	—	—	—	5.9	100	95.8
20	कोंडागाँव	4.6	98.2	97.5	—	—	—	4.6	98.2	97.5
21	बलौदाबाजार	2.7	86.2	97.6	91.7	86.2	97.6	—	—	—
22	गरियाबंद	3.6	97.2	94.0	3.5	100	94.7	3.7	95.2	93.5
23	बालोद	3.7	97.3	17.0	3.5	96.9	99.1	4.7	100	92.0
24	मुंगेली	2.7	93.1	97.5	2.7	93.1	97.5	—	—	—
25	सूरजपुर	4.3	96.1	96.1	—	—	—	4.3	96.1	96.1
26	बलरामपुर	6.1	98.6	95.9	—	—	—	6.1	98.6	95.9
27	बेमेतरा	3.3	83.3	100.0	3.3	83.3	100	—	—	—
28	गोरिला-पेण्ड्रा-मरवाही	5.0	100.0	92.0	—	—	—	5.0	100	92.0
योग		4.2	95.6	96.3	3.3	93.5	97.2	5.3	98.3	95.1

स्रोत - चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में विधालय की उपलब्धता

अनुलग्नक - 7.9

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

क्र.	जिला	राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति				गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति				अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति			
		पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक शाला है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक शाला है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है	पंचायत जहाँ केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है
1	बस्तर	6.1	62.9	13.6	12.9	—	—	—	6.1	62.9	13.6	—	12.9
2	बिलासपुर	15.2	44.8	22.8	15.9	15.2	44.8	22.8	—	—	—	—	—
3	देवड़ा	7.2	55.4	21.7	8.4	—	—	—	7.2	55.4	21.7	—	8.4
4	धमतरी	4.7	51.3	17.9	25.2	4.0	46.9	18.9	29.1	6.8	64.4	15.2	13.6
5	दुर्ग	26.9	41.2	11.9	18.1	26.9	41.2	11.9	18.1	—	—	—	—
6	जाजगीर-चापा	5.8	54.2	19.3	17.7	5.8	54.2	19.3	17.7	—	—	—	—
7	जयपुर	17.2	52.4	17.2	11.8	—	—	—	—	17.2	52.4	17.2	11.8
8	कोकर	3.6	44.9	19.6	21.0	—	—	—	—	3.6	44.9	19.6	21.0
9	कबीरधाम	13.5	58.7	14.5	12.3	13.5	58.7	14.5	12.3	—	—	—	—
10	कोरबा	11.4	59.1	17.6	9.7	—	—	—	—	11.4	59.1	17.6	9.7
11	कोरिया	11.8	51.5	21.3	13.6	—	—	—	—	11.8	51.5	21.3	13.6
12	महासमुद्र	19.2	49.4	13.1	17.3	19.2	49.4	13.1	17.3	—	—	—	—
13	रायगढ़	12.3	57.7	15.3	12.5	15.3	60.5	10.5	12.6	8.3	53.9	21.7	12.4
14	रायपुर	69.5	52.4	11.2	15.0	17.5	12.4	11.2	15.0	—	—	—	—
15	राजनांदगाव	17.4	47.8	15.2	17.4	19.9	47.0	15.2	15.6	1.4	50.0	15.1	22.6
16	सरगुजा	6.4	59.0	23.5	8.8	—	—	—	—	6.4	59.0	23.5	8.8
17	बीजापुर	37.0	37.0	14.1	7.6	—	—	—	—	37.0	37.0	14.1	7.6
18	नारायणपुर	13.9	60.5	9.3	12.8	—	—	—	—	13.9	60.5	9.3	12.8
19	सुलमा	31.2	58.3	6.2	4.2	—	—	—	—	31.2	58.3	6.2	4.2
20	कोडार्गो	6.1	54.0	20.2	91.7	—	—	—	—	6.1	54.0	20.2	15.3
21	बलोदाबाजार	16.9	45.2	16.5	19.7	16.9	45.2	16.5	19.7	—	—	—	—
22	गरियाबंद	7.0	61.0	17.0	13.0	7.9	55.3	18.4	15.8	6.4	64.5	16.1	11.3
23	बालोद	20.5	44.0	13.0	21.1	21.9	43.3	11.6	21.9	12.0	48.0	22.0	16.0
24	मुंगेली	31.2	33.7	21.8	9.4	31.2	33.7	21.8	9.4	—	—	—	—
25	सुरजपुर	14.3	55.2	15.0	10.7	—	—	—	—	14.3	55.2	15.0	10.7
26	बलरामपुर	14.6	59.8	10.5	13.2	—	—	—	—	14.6	59.8	10.5	13.2
27	बेमेतरा	22.2	40.1	17.9	19.1	22.2	40.1	17.9	9.1	—	—	—	—
28	गौरला-पेड़्या-मरवाही	10.0	54.0	19.0	14.0	—	—	—	—	10.0	54.0	19.0	14.0
योग		14.6	51.6	16.3	15	16.9	48.8	15.4	17	11.6	55	17.4	12.6

स्रोत - चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समक

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12504/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आवकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 25 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इससठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

धारा 25 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(पांच) आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. “छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के अधीन आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) अधिरोपित किया जाता है. राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्माण के अनुसार, स्थानीय निकायों के संसाधन में वृद्धि करने हेतु आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा.”
2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 30 नवम्बर, 2010

अमर अग्रवाल
व्यवसायिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

“ संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित ”

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा-25 का सुसंगत उद्धरण-

* * * * *

धारा-25 आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क :-

उप-धारा (1) :- यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में तत्सम्य विनिर्दिष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों से भिन्न आबकारी शुल्क योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहित किया जाएगा.

- (ए) जिनका आयात किया गया हो, या
- (बी) जिनका निर्यात किया गया हो, या
- (सी) जिनका परिवहन किया गया हो, या
- (डी) जो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित की गई हों, खेती में उपजाई गई हों अथवा संग्रहित की गई हों, या
- (ई) जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी में या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई किसी आसवनी या मद्य निर्माण शाल में विनिर्मित की गई हो ;

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि; वह आबकारी शुल्क योग्य किसी भी वस्तु को किसी ऐसे शुल्क से, जिसके लिये कि, वह इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो छूट दे.

उप-धारा (2) :- उप-धारा (1) के अधीन शुल्क का अधिरोपण :-

- (एक) उस स्थान के, जहां किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है, या
- (दो) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु की शक्ति (स्ट्रेन्थ) और उसकी क्वालिटी के, या
- (तीन) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग के अनुसार विभिन्न दरों से किया जा सकेगा, या
- (चार) ऐसे सिद्धान्तों पर, जो कि विहित किये जाएं, आधारित आबकारी शुल्क-योग्य वस्तुओं के मूल्य के.

* * * * *

देवेन्द्र बर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा.



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ
GOVERNMENT OF ODISHA
PANCHAYATI RAJ & DRINKING WATER
DEPARTMENT

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ - ୨୫୦୦୧

Odisha Lok Sabha Bhawan
Sachibairya Marg, Bhubaneswar-751 001
e-mail: panchraj@nic.in

No. 9252 / Date 06.06.2020
PR-SFC-POLICY-0002-2020

From
Shri Deoranjjan Kumar Singh, IAS
Principal Secretary to Government.

To
All Collectors
All Project Directors, DRDAs

Sub- Guidelines on Utilization of Devolution of funds recommended by the 5th State Finance Commission to 3 Tier PRIs for the period from 2020 - 21 to 2025 - 26 (6 years).

Madam / Sir,

I am directed to say that, on the recommendations of the 5th State Finance Commission and the Action Taken Report (ATR) thereof laid before the Odisha Legislative Assembly, the distribution of devolution of funds to 3 tier PRIs has been allowed in the ratio of 80:30:10 in favour of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad respectively to be utilised on community felt need based projects. These projects are to be included in the GPDP of the Gram Panchayat, Annual Action Plan of the Panchayat Samiti and Annual Action Plan of the Zilla Parishad for the particular year. For proper monitoring of the expenditure, the 5th PFS Application must be used which is integrated with PRIASOFT, PFMS and IFMS.

**TOTAL DEVOLUTION OF FUNDS TRANSFER TO THE 3 TIER PRIs
FOR THE PERIOD 2020-26.**

(Rs. In crore)

PRIs	Total (Per-Year)	Total Allocation (2020-21 to 2025-26)
Gram Panchayats	549.05	3294.30
Panchayat Samitis	274.53 (Tied 50% i.e. Rs. 137.265 + Untied 50% i.e. Rs. 137.265)	1647.18
Zilla Parishads	91.51	549.06
Grand Total	915.09	5490.54

[Signature]

V. MODE OF TRANSFER OF DEVOLUTION OF FUNDS AT Z.P. LEVEL:

The fund to be devolved to all Zilla Parishads comes to Rs. 549.06 crore for the period from 2020-21 to 2025-26 @ Rs.91.51 Cr. per annum. The distribution has been made to Zilla Parishads considering number of Panchayat Samities in the districts (i.e. @ Rs.29,14,331.00 per Panchayat Samiti x nos. of Panchayat Samiti in a Zilla Parishad). The allocation under Devolution of Funds on SFC to Zilla Parishad shall be transmitted to the approved SFC Account integrated in PRIASOFT with PFMS and IPMS.

5th SFC DEVOLUTION TO THE ZILLA PARISHAD :

The funds under this head provided to the Zilla Parishad may be utilized as per local needs prioritizing the works as detailed below:

1. For achieving the drinking water saturation plan of the district, new PWS/ augmentation of existing PWS (BHTC to rural household) may be taken up in convergence with other State Govt. Schemes like BASUDHA/ RIDF/ SFC, to meet O&M Cost of PWS in operation in District etc. Work may also be taken up with depositing money in the DWSM Account for making proper convergence planning.
2. Payment of Energy bill of Mega PWS operated in the District,
3. Sanitation and water supply works to the Govt. Institutions transferred to Panchayat Raj & Drinking Water Department like District Headquarter Hospital, Sub-Divisional Hospitals, CHC / PHC, District Veterinary Hospital, +2 College etc.
4. Solid waste and liquid waste management in different Panchayat Samities.
5. New Construction and Maintenance of Govt. Higher Secondary Schools (Grades up to XII)
6. Repair and maintenance of Sub-Divisional Hospital.
7. Repair and maintenance of District Headquarter Hospital.
8. Other need based community driven projects as decided by the Zilla Parishad.

28

FUND ALLOCATION

Name of Scheme: 15th FC

UNTIED Fund					
Year	No. of block	Rate	Total Allocation	No. of ZP member	Allocation per ZP member
202. -2.	5	2201272	1,10,06,360.00	14	7,86,168.57
Total			1,10,06,360.00		

TIED Fund					
Year	No. of block	Rate	Total Allocation	No. of ZP member	Allocation per ZP member
202. -2	5	3301910	1,65,09,550.00	14	11,79,253.57
Total			1,65,09,550.00		

Name of Scheme: 5th SFC

DEVOLUTION FUND					
Year	No. of block	Rate	Total Allocation	No. of ZP member	Allocation per ZP member
202. -2.	5	2914331	1,45,71,655.00	14	10,40,832.50
Total			1,45,71,655.00		

स्तरांक की गणना हेतु आवश्यक आंकड़े एवं स्तरांक के गणना की जानकारी

क्र.	संकेतक	इकाई	समको की आवश्यकता	गणना सूत्र
1	2	3	4	5
1	सभी बसाहटों में नल जल की आपूर्ति	प्रतिशत	- ग्राम पंचायत में बसाहटों की संख्या - नल जल आपूर्ति वाली बसाहटों की संख्या	$\frac{\text{ग्राम पंचायतों में कुल बसाहटों की संख्या}}{\text{नल जल आपूर्ति वाली बसाहटों की संख्या}} \times 100$
2	सभी घरों में नल जल कनेक्शन	प्रतिशत	ग्राम पंचायत में घरों एवं नल जल वाले घरों की संख्या	$\frac{\text{नल जल वाले घरों की संख्या}}{\text{ग्राम पंचायत में कुल घरों की संख्या}} \times 100$
3	प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	प्रतिशत	- ग्राम पंचायत में टंकी की क्षमता - ग्राम पंचायत की जनसंख्या	$\frac{\text{ग्राम पंचायत की टंकी की क्षमता}}{\text{ग्राम पंचायत की जनसंख्या}} \times 100$
4	प्रतिदिन नियम समय पर जल आपूर्ति	प्रतिशत	प्रतिदिन जल आपूर्ति का समय	$\frac{\text{नियत समय पर जल आपूर्ति वाले दिन}}{\text{जल आपूर्ति के कुल दिन}} \times 100$
5	जल आपूर्ति संबंधी विद्युत देयक का प्रतिमाह भुगतान	प्रतिशत	विद्युत देयक भुगतान की जानकारी	$\frac{\text{विद्युत देयक भुगतान वाले माह की संख्या}}{\text{कुल माह}} \times 100$
6	स्वच्छ जल आपूर्ति	प्रतिशत	जल परीक्षण संबंधी आंकड़े	$\frac{\text{उत्तीर्ण परीक्षणों की संख्या}}{\text{कुल परीक्षण की संख्या}} \times 100$
7	जल आपूर्ति सेवा की लागत वसूली	प्रतिशत	- जल आपूर्ति पर संधारण व्यय - जल कर से प्राप्त कुल राशि	$\frac{\text{जल कर से प्राप्त कुल राशि}}{\text{जल आपूर्ति पर कुल संधारण व्यय}} \times 100$
8	ग्राम पंचायत के सभी घरों में शौचालय है	प्रतिशत	- घर में शौचालय वाले घरों की संख्या - कुल घरों की संख्या	$\frac{\text{घर में शौचालय वाले घरों की संख्या}}{\text{कुल घरों की संख्या}} \times 100$
9	सभी घरेलू शौचालय उपयोग योग्य है	प्रतिशत	- शौचालय के लिए घर से बाहर जाने वाले परिवारों की संख्या - घर में शौचालय वाले परिवारों की संख्या	$\left[100 - \frac{\text{शौचालय के लिए घर से बाहर जाने वाले परिवारों की संख्या}}{\text{घर में शौचालय वाले परिवारों की संख्या}} \times 100 \right]$

1	2	3	4	5
10	सभी घरों से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है।	प्रतिशत	- घर से कचरा लिये जाने वाले घरों की संख्या - कुल घरों की संख्या	$\frac{\text{कुल घरों की संख्या}}{\text{कुल घरों की संख्या}} \times 100$
11	एकत्रित कचरे का युक्तियुक्त निराकरण		कचरे के पृथक्करण से संबंधित आंकड़े	$\frac{\text{पृथकीकृत कचरे की मात्रा}}{\text{कुल कचरे की मात्रा}} \times 100$
12	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की लागत	प्रतिशत	- स्वच्छता कर वसूली की कुल राशि - स्वच्छता कर पर कुल संधारण व्यय	$\frac{\text{स्वच्छता पर कुल संधारण व्यय}}{\text{स्वच्छता कर से वसूली की कुल राशि}} \times 100$
13	सभी आंतरिक पक्की सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ हैं।	प्रतिशत	- पक्की सड़कों की कुल लंबाई - पक्की सड़कों के दोनों ओर नाली वाली सड़कों की लंबाई	$\frac{\text{कुल पक्की सड़कों की लंबाई}}{\text{कुल पक्की सड़कों की लंबाई}} \times 100$
14	सभी कच्ची पक्की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है।	प्रतिशत	- कच्ची/पक्की सड़कों की कुल लंबाई - स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों की कुल लंबाई	$\frac{\text{कच्ची पक्की सड़कों की कुल लंबाई}}{\text{स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों की कुल लंबाई}} \times 100$
15	स्ट्रीट लाइट विद्युत देयक का प्रतिमाह भुगतान हो रहा है	प्रतिशत	स्ट्रीट लाइट विद्युत देयक के प्रतिमाह भुगतान की जानकारी	$\frac{\text{स्ट्रीट लाइट विद्युत देयक भुगतान वाले माह की संख्या}}{12 \text{ माह}} \times 100$
16	स्ट्रीट लाइट के संधारण व्यय की वसूली	प्रतिशत	- स्ट्रीट लाइट के संधारण व्यय की कुल वसूली - प्रकाश शुल्क वसूली की राशि	$\frac{\text{स्ट्रीट लाइट पर कुल संधारण व्यय}}{\text{प्रकाश शुल्क वसूली की राशि}} \times 100$

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या

वर्ष	कुल जनसंख्या	शहरी		ग्रामीण	
		जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
2011	25545000	5937000	23.24	19608000	76.76
2021	29493000	7810000	26.48	21683000	73.52
2025	30867000	8568000	27.76	22299000	72.24
2026	31211000	8763000	28.08	22448000	71.92
2027	31512000	8948000	28.40	22564000	71.60
2028	31814000	9135000	28.71	22679000	71.29
2029	32116000	9324000	29.03	22792000	70.97
2030	32417000	9515000	29.35	22902000	70.65

Source: Report of the Technical Group on Population Projection, National Commission on Population, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, July 2020

ग्राम पंचायतों के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय की गणना

1. प्रति व्यक्ति स्ट्रीट लाईट व्यय		
एक ग्राम पंचायत में कुल स्ट्रीट लाईट की आवश्यकता	=	प्रति ग्राम पंचायत सड़कों की औसत $\times$ बिजली के दो खम्भों के बीच की दूरी
	=	12,350 मी. (12.35 किमी.) $\div$ 50 मीटर
	=	247
प्रति ग्राम पंचायत कुल आवश्यक राशि	=	स्ट्रीट लाईट इकाईयों की संख्या $\times$ प्रति यूनिट संभावित लागत
	=	247 $\times$ 1500
	=	रु. 3,70,500
प्रति व्यक्ति व्यय	=	प्रति ग्राम पंचायत कुल आवश्यक व्यय $\times$ प्रति ग्राम पंचायत औसत जनसंख्या
	=	3,70,500 $\div$ 1681
	=	रु. 220
2. प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यय		
प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यय	=	रु. 70 (ग्राम पंचायतों द्वारा 2017-18 से 2021-22 के बीच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर औसत पूंजीगत व्यय रु. 70 प्रतिवर्ष किया गया है। उसे ही अधिनिर्णय अवधि के लिये अनुमानित राशि का अनुमान लगाने के लिये मान्य किया गया है।)
3. सड़कों पर प्रति व्यक्ति व्यय		
प्रति ग्राम पंचायत औसत कच्ची सड़कें	=	7.07 किमी.
ग्राम पंचायतों में अनुमानित कुल कच्ची सड़कों की लंबाई	=	ग्राम पंचायतों की संख्या $\times$ प्रति ग्राम पंचायत औसत कच्ची सड़कें
	=	11664 $\times$ 7.07 कि.मी.
	=	82,464.48 कि.मी.

कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिये कुल राशि की आवश्यकता	=	कुल अनुमानित कच्ची सड़कों की लंबाई	x	प्रति कि.मी. सीसी सड़क की लागत (3मी.चौड़ी x 6 इन्च मोटी)
	=	82,464.48	x	रु. 25 लाख
	=	रु. 20,616.12 करोड		
कच्ची आंतरिक सड़कों / गलियों को पक्का करने की प्रति व्यक्ति लागत	=	कुल अनुमानित कच्ची सड़कों को पक्क करने की कुल लागत	÷	2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या
	=	रु. 20,616.12 करोड़	÷	1,96,08,000
	=	रु. 10,514		
4. प्रति व्यक्ति नाली निर्माण व्यय				
नाली निर्माण की प्रति ग्राम पंचायत औसत आवश्यकता	=	7.07 कि.मी. सड़कों के दोनो तरफ (प्रति ग्राम पंचायत 7.07 कि.मी. कच्ची सड़कें हैं जिन्हें पक्का किया जाना है)		
कुल आवश्यक नाली निर्माण की लंबाई	=	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	x	नाली निर्माण की प्रति ग्राम पंचायत औसत आवश्यकता
	=	11,664	x	7.07
	=	82,464.48 कि.मी.		
कुल आवश्यक नाली निर्माण हेतु आवश्यक राशि	=	कुल आवश्यक नाली निर्माण की लंबाई	x	प्रति कि.मी. निर्माण लागत
	=	82,464.48 कि.मी.	x	रु. 20 लाख प्रति कि.मी.
	=	रु. 16,492.80 करोड़		
नाली निर्माण हेतु प्रति व्यक्ति आवश्यक राशि	=	नाली निर्माण हेतु कुल आवश्यक राशि	÷	2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या
	=	रु. 16,492.80 करोड	÷	1,96,08,000
	=	रु. 8,411 रुपए		

नगरीय निकायों के बकाया कच्ची सड़कों को पक्का करने की लागत

(राशि राशि रू. में)
(लंबाई कि.मी. में)

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	नगरीय निकायों में कच्ची सड़कों की अनुमानित लंबाई	नगरीय निकायों में पक्की सड़कों की अनुमानित लंबाई	नगरीय निकायों में सड़कों की अनुमानित कुल लंबाई	कच्ची सड़कों को पक्का करने की प्रति कि.मी. निर्माण लागत	कच्ची सड़कों की अनुमानित निर्माण लागत
1	नगर पालिक निगम	1232	4838	6070	6.00	7392.00
2	नगर पालिक परिषद	166	1726	1892	6.00	996.00
3	नगर पंचायत	505	2503	3008	6.00	3030.00
	योग	1903	9067	10970		11418.00

नगरीय निकायों में बकाया नाली रहित सड़कों पर नाली बनाने की लागत

(राशि करोड़ रु. में)
(लंबाई कि.मी. में)

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	सड़कों की अनुमानित लंबाई	सड़क किनारे नाली की सुविधा वाली सड़कों का प्रतिशत	नाली सुविधा रहित सड़कों का प्रतिशत	नाली सुविधा रहित सड़कों की लंबाई	प्रति कि.मी. नाली निर्माण लागत	बकाया नाली बनाने की लागत
1	नगर पालिक निगम	6070	87.25	12.75	774	4.00	3096.00
2	नगर पालिक परिषद	1892	73.70	26.30	498	4.00	1992.00
3	नगर पंचायत	3008	54.71	45.29	1362	4.00	5448.00
	योग	10970	76.65	23.35	2634		105360.00

बकाया प्रकाश रहित सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की लागत

(राशि राशि रु. में)
(लंबाई कि.मी. में)

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	सड़कों की अनुमानित लंबाई	प्रकाश सुविधा वाली सड़कों की लंबाई का प्रतिशत	प्रकाश सुविधा रहित सड़कों की लंबाई का प्रतिशत	प्रकाश सुविधा रहित सड़कों की लंबाई	प्रति कि.मी. स्ट्रीट लाइट की संख्या	कुल आवश्यक स्ट्रीट लाइट की संख्या	प्रति स्ट्रीट लाइट लागत	आवश्यक स्ट्रीट लाइट्स की कुल लागत
1	नगर पालिक निगम	6070	79.74	20.26	1230	25	30750	2000	61500000
2	नगर पालिक परिषद	1892	76.83	23.17	438	25	10950	2000	21900000
3	नगर पंचायत	3008	77.51	22.49	676	25	16900	2000	33800000
	योग	10970	78.61	21.39	2344		58600		117200000

1 प्रति कि.मी. अनुमानित 25 खम्भे/लाइट्स

नगरीय निकायों की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय

(शशि रू. में)

प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय	2011 नगरीय निकायों की कुल जनसंख्या	वर्ष 2025 नगरीय निकायों की अनुमानित जनसंख्या	वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2025 में बढ़ने वाली शहरी जनसंख्या	बढ़ने वाली शहरी जनसंख्या के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय
27257	5937000	85,68,000	26,31,000	71,71,31,67,000

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत से प्राप्तिया

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग	पांच वर्षों का औसत	निकायों की स्वयं से स्रोत से औसत आय	कुल अनुमानित प्राप्तियाँ
1	ग्राम पंचायत	29.45	31.47	34.04	33.77	34	162.73	32.55	0.01	63.78
2	जनपद पंचायत	3.8	3.2	4.00	2.28	3.7	16.98	3.40	0.03	4.96
3	जिला पंचायत	0.2	0.05	0.06	0.06	0.06	0.43	0.09	0.00	0.13
	योग	33.45	34.72	38.10	36.11	37.76	180.14	36.03	0.04	68.86

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मर्दों में वास्तविक प्राप्तियाँ (वर्ष 2017-18 से 2021-22)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.	विवरण	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	कुल	वार्षिक औसत प्राप्तियाँ
1	समनुदेशित प्राप्तियाँ	274.77	61.81	183.17	176.13	314.17	1010.05	202.01
2	अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
3	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ	945.72	839.07	748.47	617.93	880.26	4031.44	806.29
4	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्तियाँ	1022.18	1047.86	1415.89	1454.00	1075.00	6014.93	1202.99
	कुल राशि	2242.67	1948.74	2347.53	2248.06	2269.43	11056.42	2211.28

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

पंचायती राज संस्थाओं की 2025-26 से 2029-30 तक विभिन्न मदों से संभावित (प्रक्षेपित) प्राप्तियां

राशि करोड़ रू में)

क्र.	विवरण	पांच वर्षों की औसत वार्षिक प्राप्तियां (2017-18 से 2021-22)	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	योग (2025-26 से 2029-30)
1	स्वयं के स्रोतों से आय	68.86	75.75	83.32	91.65	100.82	110.90	121.99	134.19	147.61	615.50
2	समनुदेशित प्राप्तियां	202.01	222.21	244.43	268.88	295.76	325.34	357.87	393.66	433.03	1805.66
3	अनुदान										
	योग	270.87	297.96	327.75	360.53	396.58	436.24	479.86	527.85	580.63	2421.17
4	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के प्राप्ति	806.29	886.92	975.61	1073.17	1180.49	1298.54	1428.39	1571.23	1728.35	7207.00
5	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्ति	1202.99	1323.29	1455.62	1601.18	1761.30	1937.43	2131.17	2344.29	2578.72	10752.90
	योग	2280.15	2508.17	2758.98	3034.88	3338.37	3672.20	4039.42	4443.37	4887.70	20381.07

नगरीय निकायों की स्वयं की स्रोत से कुल आय

(राशि करोड़ रु में)

क्र.	विवरण	स्वयं के स्रोत से आय						न्यादर्श निकायों की संख्या	निकायों की स्वयं के स्रोत के औसत आय	निकायों की कुल संख्या	निकायों की स्वयं के स्रोत से कुल अनुमानित आय
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग				
1	नगर पालिक निगम	279.89	287.23	275.03	303.73	359.08	1504.96	300.992	43.00	14	601.98
2	नगर पालिका परिषद	44.99	41.58	37.21	48.49	48.13	220.4	44.08	1.70	44	74.60
3	नगर पंचायत	22.27	22.37	18.87	23.58	24.64	111.73	22.346	0.46	112	51.08
	योग	347.15	351.18	331.11	375.8	431.85	1837.09	367.418	45.15	170	727.66

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ (वर्ष 2017-18 से 2021-22)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.	विवरण	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	कुल	वार्षिक औसत प्राप्तियाँ
1	समनुदेशित प्राप्तियाँ	75.55	49.02	71.98	77.42	102.45	376.42	75.28
2	अनुदान	1275.56	840.14	1048.97	1048.97	1010.31	5223.96	1044.79
	योग (1+2)	1351.11	889.16	1120.95	1126.40	1112.76	5600.38	1120.08
3	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ	441.55	299.76	320.73	441.62	451.45	1955.11	391.02
4	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्तियाँ	243.80	282.04	451.56	403.50	530.00	1910.90	382.18
	कुल राशि	2036.46	1470.95	1893.25	1971.52	2094.21	9466.39	1893.28

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों की 2025-26 से 2029-30 तक विभिन्न मदों से संभावित (प्रक्षेपित) प्राप्तियां

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.	विवरण	पांच वर्षों की औसत वार्षिक प्राप्तियां (2017-18 से 2021-22)	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	योग (2025-26 से 2029-30)
1	स्वयं के स्रोतों से आय	727.66	800.43	880.47	968.52	1065.37	1171.90	1289.09	1418.00	1559.80	6504.17
2	समनुदेशित प्राप्तियां एवं अनुदान	1120.07	1232.08	1355.29	1490.82	1639.9	1803.88	1984.27	2182.7	2400.97	15209.98
3	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के प्राप्ति	391	430.10	473.11	520.42	572.46	629.71	692.68	761.95	838.14	3494.94
4	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्ति	382.18	420.40	462.44	508.68	559.55	615.50	677.06	744.76	819.24	3416.11
	योग	2620.91	2883.00	3171.30	3488.43	3837.27	4221.00	4643.10	5107.41	5618.15	23426.94

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

स्थानीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में देय / कर / उपकर अधिभार राशि

(राशि करोड़ रूप में)

क्र	विवरण	वास्तविक					मध्य अवधि					10% वार्षिक वृद्धि के आधार पर प्रक्षेपित मूल्य					योग
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30			
1	स्टाम्प शुल्क	69	73.74	126.79	136.90	172.45	189.70	208.67	229.54	252.49	277.74	305.51	336.06	369.67	1541.47		
2	वस्तु एवं सेवा कर	4386.56	8203.41	7894.82	7925.01	9483.48	11795.96	13565.35	15600.15	17940.18	20631.21	23725.89	27284.77	31377.49	120959.54		
3	वस्तु एवं सेवा कर के 7.72 प्रतिशत राशि									1529.68	1682.64	1850.91	2036.00	2239.60	9338.83		
4	आबकारी शुल्क में अधिभार	281.88	318.81	323.04	246.18	261.27	287.40	316.14	347.75	382.53	420.78	462.86	509.14	560.06	2335.36		
5	ग्रामीण विकास निधि	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150.00		
योग		4767.44	8625.95	8374.65	8338.10	9947.20	12303.06	14120.16	16207.44	2194.69	2411.16	2649.28	2911.20	3199.33	13365.66		

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के अधिकारी / कर्मचारीगण

1. अध्यक्ष, श्री सरजियस मिंज
2. सचिव, श्री सतीश पाण्डेय
3. संयुक्त सचिव, श्री जसमिंदर सिंह विरदी
4. अनुसंधान अधिकारी, सुश्री पायल गुप्ता
5. लेखक, श्री माधव हरदेवी
6. निज सचिव, श्री एम.एन. राजुरकर
7. सहा. ग्रेड 02, श्री अशोक कुमार कावड़े
8. सहा. ग्रेड 03, श्री जैनेन्द्र वैष्णव
9. कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री अमित पंसारी
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री गिरीश कुमार साहू
11. कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री शुभम पंसारी
12. वाहन चालक, श्री दीपक कुमार जोल्हे
13. वाहन चालक, श्री गंगाधर साहू
14. वाहन चालक, श्री प्रमोद साहू
15. भृत्य, श्री चन्द्रशेखर वर्मा
16. भृत्य, श्री गणेश्वर पटेल
17. भृत्य, श्री कौशिक बिहारी
18. भृत्य, श्री संदीप कुमार दिवाकर
19. भृत्य, श्री बैसाखु राम

